संख्या-34/2020/डी-385/38-2-2020-2(15)डी/2018

प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 08 सितम्बर, 2020**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशासन) योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0ओ0-229/लेखा पैंशन/डी0आर0डी0ए0/प्रशा0/2020-21, दिनांक 04 अगस्त, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशासन) योजनान्तर्गत डीआरडीए कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान हेतु केन्द्रांश अवमुक्त सम्बन्धी भारत सरकार के पत्र संख्या-आर-17014/01/2020-21-डीआरडीए (एसएल नं0-16), दिनांक 29 जुलाई, 2020 संलग्न करते हुए सन्दर्भित पत्र के अनुसार कुल धनराशि रू0 1342.31 लाख (रूपये तेरह करोड़ बयालीस लाख इक्कतीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशासन) योजनान्तर्गत धनराशि रू0 10000.00 लाख के बजट प्रावधान के सापेक्ष कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान हेतु भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 29 जुलाई, 2020 में जनपदवार उल्लिखित धनराशि रू0 1342.31 लाख (रूपये तेरह करोड़ बयालीस लाख इक्कती हजार मात्र) आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय एवं स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण स्वीकृत धनराशि की सीमा तक किया जायेगा तथा आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास को दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य सरकार एवं भारत सरकार को समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2021 को समर्पित कर दी जायेगी।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-0202-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के.60/रा.40-के.+रा.)-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशा0 पत्र संख्या-ई0ओ0-ई-2-677/दस-2020, दिनांक 08 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव।

<u>संख्या-34/2020/ डी-385/38-2-2020 तददिनांक।</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनु0-3
6- ग्राम्य विकास अनु0-3
7- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।